

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही (राज.)

बईजलारा श्रीमती अल्पा चौधरी, आई.ए.एस.

प्रार्थना-पत्र संख्या 23/2025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
प्राधिकृत अधिकारी असेट री-कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड मुम्बई शाखा कार्यालय नई दिल्ली जरिए प्राधिकृत अधिकारी श्री वीरेन्द्र यादव।		1. श्री पुखराज पुत्र स्व. श्री सीताराम निवासी पाडीव तहसील व जिला सिरौही। 2. श्रीमती सुकीदेवी पत्नि श्री पुखराज निवासी पाडीव तहसील व जिला सिरौही। 3. श्री प्रभूराम हीरागर पुत्र श्री नारायणलाल निवासी खंडरा तहसील शिवगंज जिला सिरौही। 4. श्री मंछाराम पुत्र श्री केसाजी निवासी एनएसपी स्कूल रोड नवा वास, सिरौही।

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइडेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल  
एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002

उपरिथिति :-

1. अधिवक्ता श्री चन्द्रसिंह राठौड, प्रार्थी बैंक की ओर से।



निर्णय

दिनांक : 19.05.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्युराइडेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्युरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया।

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी पक्ष के द्वारा अप्रार्थी

1. श्री पुखराज पुत्र स्व. श्री सीताराम निवासी पाडीव तहसील व जिला सिरौही।
2. श्रीमती सुकीदेवी पत्नि श्री पुखराज निवासी पाडीव तहसील व जिला सिरौही।
3. श्री प्रभूराम हीरागर पुत्र श्री नारायणलाल निवासी खंडरा तहसील शिवगंज जिला सिरौही।
4. श्री मंछाराम पुत्र श्री केसाजी निवासी एनएसपी स्कूल रोड नवा वास, सिरौही।

को राशि रुपये 3,50,000/- की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई तथा पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पारा बतौर अमानत बंधक रखी थी। अप्रार्थी श्री पुखराज पुत्र स्व. श्री सीताराम ने अपनी जायदाद आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 15 दिनांक 28.07.1982 प्लॉट नम्बर 15 जो कि ग्राम पाडीव तहसील सिरौही में स्थित है, जिसकी माप 1350 वर्गफीट है, को बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन कर दिया।

जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही

:: 2 ::

अप्रार्थी द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी के बैंक/कम्पनी को ऋण का भुगतान करने में असाफल्य रहने पर प्रार्थी द्वारा ऋण राशि गय ब्याज के अदा करने हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी के नाम रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से नोटिस दिनांक 02.12.2024 को जारी किये गये, जो पंजीकृत डाक/अखबार में प्रकाशन के माध्यम से तागिल करवाये गये उसके पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि गय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीयों के द्वारा बतौर जमानत रहन रखी गई सम्पति इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

प्रार्थी के लायक अधिकारी/अधिवक्ता की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता/अधिकारी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित विन्दुओं की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी एक नियमित निकाय है जो अपनी शाखाओं के माध्यम से ऋण देने का व्यवसाय करती है उसकी शाखाओं में से एक नई दिल्ली में भी स्थित व कार्यरत है। प्रार्थी बैंक/संस्था द्वारा अप्रार्थीगण को रुपये 3,50,000/- का ऋण स्वीकृत किया था। जिसकी एवज में अपनी जायदाद बैंक/कम्पनी के पक्ष में बन्धक रखी गई थी जिसका वर्णन प्रार्थना पत्र में किया गया है। बहस में कहा कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी पक्ष को नियमित रूप से ऋण राशि व ब्याज राशि का भुगतान नहीं करने के कारण एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये किन्तु अप्रार्थी द्वारा देय ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया। भुगतान नहीं करने के फलस्वरूप अप्रार्थी स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक/कम्पनी के पक्ष में रहन रखी गई उक्त जायदाद इत्यादि का कब्जा प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाया जावे।

प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी। अप्रार्थी द्वारा राशि रुपये 3,50,000/- का ऋण लिया था। ऋण राशि के बदले में अप्रार्थी द्वारा अपनी जायदाद को बैंक/कम्पनी के पक्ष में उक्त जायदाद रहन रखी है। प्रार्थी द्वारा नियमानुसार धारा 13(2) के अधीन अप्रार्थी को रजिस्टर्ड नोटिस भी दिनांक 02.12.2024 को जारी किये है जिनकी प्राप्ति के पश्चात् भी अप्रार्थी द्वारा देय राशि का भुगतान नहीं किया है।

दी सिक्कुराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्कुरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 की धारा 14 निम्न प्रकार है :-

14. Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset – (1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be transferred by the secured creditor under the provisions of this Act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession or control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within whose jurisdiction any such secured asset or other document, relating thereto may be situated or to take possession thereof and the



जिला मजिस्ट्रेट, गुर्गाँव

Chief Metropolitan Magistrate or as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him –

- (a) take possession of such asset and documents relating thereto and  
(b) forward such assets and documents to the secured creditor

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1), the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may be take or cause to be taken such steps and use, or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

परिणामस्वरूप तथ्यों के संदर्भ में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्कुराइटेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एस्सेट्स एण्ड एन्फोर्समेन्ट आफ सिक्कुरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ने अपनी जायदाद बैंक के पास बतौर अमानत बंधक रखी थी। अप्रार्थी श्री पुखराज पुत्र स्व. श्री सीताराम ने अपनी जायदाद आवासीय सम्पत्ति पट्टा संख्या 15 दिनांक 28.07.1982 प्लॉट नम्बर 15 जो कि ग्राम पाडीव तहसील व जिला सिरोही में स्थित है, जिसकी माप 1350 वर्गफीट है, को बैंक/कम्पनी पक्ष में रहन कर दिया। जिसका अडौस-पडौस इस प्रकार है-

पूर्व- श्री पूनाराम का प्लॉट।  
पश्चिम- श्रीमती पूनीबाई क प्लॉट।  
उत्तर- खालसा गली।  
दक्षिण- आम रास्ता व दरवाजा।

उपरोक्त जायदाद पर अन्य किसी न्यायालय का स्थगन नहीं होने की स्थिति में उक्त जायदाद का कब्जा अप्रार्थी से प्राप्त कर जरिये संबंधित पुलिस थाना से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को संभलाये जाने का आदेश दिया जाता है। यदि उक्त सम्पत्ति किसी भी तरीके से बंद पायी जाती है, तो ताला तोड़कर उक्त सम्पत्ति पर प्रार्थी बैंक अपना कब्जा स्थापित करें। आदेश की प्रति वास्ते पालनार्थ पुलिस अधीक्षक सिरोही, संबंधित थानाधिकारी पुलिस थाना एवं प्रार्थी बैंक/कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। उक्त आदेश दिनांक 31.07.2025 के बाद से प्रभावी होगा। आदेश आज दिनांक 19.05.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।



*अल्पा चौधरी*  
(अल्पा चौधरी)  
जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही